# प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा का महत्व

डॉ. संजीव कुमार *

भारत में नई सरकार के एक वर्ष पूरा होने से पहले, 14-16 मई, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा, उत्पादक और महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रीमियर ली केकियांग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता ने यात्रा के दौरान कुल 50 सरकारी और व्यावसायिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के रूप में मूर्त परिणाम दिए। राष्ट्रपति शी और प्रीमियर ली के साथ उनकी अपेक्षाकृत लंबे समय की बातचीत ने एक सकारात्मक संदेश दिया। इसके अलावा, यात्रा के दौरान जारी किए गए दो संयुक्त बयान और भारतीय नेता के मीडिया वक्तव्य और बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय तथा शंघाई में भारत-चीन व्यापार मंच में दिए गए भाषण सहित पांच प्रमुख बयानों/भाषणों के दौरान उठाए गए मुद्दों सहित, दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों और सरोकार के मुद्दों पर ठोस बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृह शहर और चीन के शानक्सी प्रांत की राजधानी शीआन से अपनी तीन दिवसीय यात्रा शुरू की। बौद्ध मंदिर में अत्यंत उत्साह सहित अतिथि नेता का पारंपरिक तांग राजवंशीय स्वागत किया गया। शीआन भारत और चीन के दो-तरफा सांस्कृतिक संपर्कों के पदचिह्नों का प्रतीक है। सांस्कृतिक कूटनीति ने दो सभ्य राज्यों के बीच आध्यात्मिकता, शिक्षा, कला और व्यापार के आधार पर द्विपक्षीय सभ्यता संबंधी संबंधों का पता लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

मूर्त परिणामों के संदर्भ में, दोनों सरकारों के विभिन्न विभागों के बीच सहयोग के विविध क्षेत्रों से संबंधित चौबीस समझौते/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें चेंगदू और चेन्नई में वाणिज्य दूतावासों की स्थापना; रेलवे क्षेत्र, अंतरिक्ष, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास सहित शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य योजना, राज्य/प्रांतीय नेताओं के एक मंच की स्थापना, सहयोगी राज्य/प्रांत और शहरों में संबंधों की स्थापना, भारत-चीन चिंतक मंच और खनन और खनिज संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग शामिल थे।

इसके अलावा, दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के बीच छब्बीस व्यावसायिक समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौतों/समझौता ज्ञापनों का कुल मूल्य 22 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक है। ये समझौते बिजली के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, इस्पात और छोटे और मध्यम उद्यम सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैले हुए हैं।

सीमा के प्रश्न पर, संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, "दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि सीमा प्रश्न का शीघ्र समाधान दोनों देशों के बुनियादी हितों को पूरा करता है।" इसमें एक 'सक्रिय तरीके से' सीमा प्रश्न के 'राजनैतिक समाधान' की तलाश करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। यह समझते हुए कि भारत और चीन के बीच सीमा एक मुख्य मुद्दा है, निश्चित रूप से सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने "चीन के कुछ मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो हमें हमारी साझेदारी का पूरा लाभ उठाने से पीछे रखते हैं।"

उल्लेखनीय है कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के प्रयासों के अंतर्गत अधिक सीमा पर तैनात लोगों के बीच अधिक मेल-मिलाप का फैसला किया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सीमा जैसे जटिल मुद्दों पर बड़ी सफलता की अपेक्षा नहीं की गई थी। हालाँकि, भारत के दृष्टिकोण से यात्रा की सफलता संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात करने में निहित है। 'सीमा विवाद के शीघ्र समाधान' पर आम सहमति इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि चीनी नेताओं ने सीमा के मुद्दे को एक तरफ रखते हुए, अन्य मुद्दों, विशेष रूप से प्राथमिकता के साथ आर्थिक मुद्दों से निपटने पर जोर दिया।

यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की आर्थिक साझेदारी स्थापित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, "चीन और भारत की यह औद्योगिक साझेदारी हमारे लोगों के निवेश, रोजगार और संतुष्टि को बढ़ा सकती है।" शंघाई में हस्ताक्षरित व्यापार समझौतों के अनुसार बड़ी संख्या चीनी कंपनियां भारत में निवेश करने और भारत में नई सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में योगदान के लिए उत्सुक है। हालाँकि, चीन के साथ भारत के विशाल (40 करोड़ अमरिकी डॉलर) व्यापारिक घाटे के मुद्दे पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। भारत के लिए बाजार पहुंच और फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे भारतीय उत्पादों के लिए गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने के मुद्दे पर काम करने की जरूरत है। भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह तंत्र को दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक समन्वय के लिए काम करने का सुझाव दिया गया है।

भारत और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक आधार पर लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। इस यात्रा में राज्यों/प्रांतों, शहरों और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भारत-चीन राज्य/प्रांतीय नेताओं के पहले मंच में गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की भागीदारी एक स्वागत योग्य कदम था। सहयोगी प्रांत और सहयोगी शहर संबंधों की स्थापना और चीनी पर्यटकों के लिए ई-वीजा की घोषणा - सभी को लोगों के आपसी आदान-प्रदान को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को दूर कर आर्थिक सहयोग का पोषण करते हुए जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

चीन के साथ भारत के संबंध जटिल है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दोनों देशों के लिए 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। एक तिहाई मानवता की आबादी के साथ, भारत और चीन दोनों अपने घरेलू परिवर्तन को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई है। इसके अलावा, दोनों देशों के लोगों के जानकारी के अंतर और आपसी धारणा में सुधार करके अधिक तालमेल सुनिश्चित करने के लिए इसने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब, दोनों देशों के नेताओं द्वारा इन सहमतियों को ठोस नतीजों में बदलना दोनों देशों के लिए असली परीक्षा होगी। द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर जोर देने को अधिक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और चीन के बीच आर्थिक साझेदारी एशिया के आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।"

*****

*डॉ. संजीव कुमार, भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं*

*

*अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।*